लेटर्स पेटेंट अपील

प्रेम चंद पंडित और एसएस संधावालिया न्यायमूर्ति के समक्ष

चेतन दास, - *अपीलकर्ता।*

बनाम

मारू और अन्य - *उत्तरदाता*

1970 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 270

18 दिसंबर, 1970

*पंजाब भूमि अवधि सुरक्षा अधिनियम (*1953 *का X) - धारा* 2 (3), *परंतुक (ii) (6)* और स्पष्टीकरण - परंतुक *(यह)* के दायरे में "विस्थापित व्यक्ति" - *क्या वह आवंटी होना चाहिए जिसे भूमि मूल रूप से आवंटित की गई है - मूल आवंटी जो किसी अन्य आवंटी से अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त करता है। विस्थापित व्यक्तियों को दिए गए बड़े अनुमेय क्षेत्र का अधिभोग - चाहे वह ऐसे आवंटी पर लागू हो - मकान मालिक को अनुमेय क्षेत्र का आरक्षण किए बिना यह प्रमाणित किए बिना कि वह एक छोटा भू-स्वामी है - क्या बड़ा भूस्वामी घोषित होने पर आरक्षण करने का हकदार है।.*

यह माना गया कि पंजाब भूमि अवधि सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 2 (3) के परंतुक (ii) के खंड (बी) के दायरे में एक "विस्थापित व्यक्ति" वह होगा जिसे अधिकारियों द्वारा मूल रूप से भूमि आवंटित की गई है। इस प्रावधान की सरल भाषा में यह कल्पना की गई है कि विस्थापित व्यक्ति वह होना चाहिए जिसे पहला आवंटन मूल रूप से किया गया हो। परंतुक में वाक्यांश "जिसे भूमि आवंटित की गई है" इसके दायरे में मूल आवंटी के उत्तराधिकारी को शामिल नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसा उत्तराधिकारी विरासत से अपना खिताब प्राप्त करता है, न कि आवंटन से। एक आवंटी से विरासत मूल आवंटी द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष आवंटन से अलग है और दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 2 (3) (ii) के स्पष्टीकरण में स्पष्ट शब्दों में स्थिति स्पष्ट की गई है कि विस्थापित व्यक्तियों को क़ानून द्वारा दी गई एक बड़े अनुमेय क्षेत्र की रियायत केवल मूल आवंटियों के लिए है, न कि उनके उत्तराधिकारियों के लिए। इसलिए परंतुक (ii) की रियायत उन विस्थापित व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों पर लागू नहीं होगी जिन्हें मूल रूप से भूमि आवंटित की गई थी।

(पैरा 4 और 6)

यह माना गया है कि जहां कोई जमींदार, अपने अनुमेय क्षेत्र का कोई आरक्षण या चयन किए बिना,

इस दृढ़ स्थिति पर विश्वास करता है कि वह वास्तव में एक छोटा भूस्वामी है, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने अनुमेय क्षेत्र का आरक्षण करने का हकदार है जब उसे एक बड़ा भूस्वामी घोषित किया जाता है।

(पैरा 11)

माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन के निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड X के तहत पेटेंट अपील 30 मार्च 1970 को 1968 की सिविल रिट संख्या 209 में पारित की गई थी।

राम रंग, अपीलकर्ता के वकील।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए सी.डी. दीवान, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा.

डी.एस. कांग, उत्तरदाता नंबर 1 के लिए एक वकील

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, न्यायमूर्ति —1. एक विस्थापित भूस्वामी के अनुमेय क्षेत्र की सीमा क्या है, जो अपने अधिकार में आवंटित भूमि रखते हुए, विरासत के रूप में भूमि के एक अतिरिक्त क्षेत्र का अधिग्रहण करता है - यह प्राथमिक प्रश्न है जिस पर लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत इन दो संबद्ध अपील संख्या 270 और 271 में बहस की गई है। तथ्य (जो विवाद में नहीं हैं) और कानून के बिंदु समान हैं और टीम के वकील सहमत हैं कि यह निर्णय इन दोनों अपीलों को नियंत्रित करेगा।.

2. एलपीए संख्या 270 में तथ्यों का एक संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगा। अपीलकर्ता चेतन दास को 1949 में हिसार जिले के तहसील फतेहाबाद के कुलेरी गांव में विस्थापित व्यक्ति के रूप में एक मानक एकड़ और 14 यूनिट खाली जमीन आवंटित की गई थी। अपीलकर्ता के पिता सूबा मल को मीरपुर गांव में विस्थापित व्यक्ति के रूप में 70 स्टैंडर्ड एकड़ और 14 इकाइयां भी आवंटित की गई थीं। 16 दिसंबर, 1949 को सूबा मल की मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद उपरोक्त आवंटन अपीलकर्ता और उसके भाई को समान शेयरों में विरासत में मिला। इसलिए, अपीलकर्ता की कुल होल्डिंग 37 मानक एकड़ और 5-7/8 यूनिट भूमि थी। प्रतिवादी, जो किरायेदार हैं, 8 साल से अधिक समय से अपीलकर्ता के स्वामित्व में आने वाली भूमि पर खेती कर रहे थे और उन्होंने इसे खरीदने के लिए पंजाब भूमि सुरक्षा अधिनियम (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 18 के तहत आवेदन दायर किए। इन आवेदनों को सहायक कलेक्टर, फतेहाबाद ने 16 सितंबर, 1966 के अपने आदेश द्वारा अनुमति दी थी। अपीलकर्ता ने कलेक्टर के समक्ष उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसे 7 दिसंबर 1966 को खारिज कर दिया गया। इस अस्वीकृति के खिलाफ एक संशोधन को

10 मई 1967 के अपने आदेश द्वारा अंबाला डिवीजन के आयुक्त के समक्ष इसी तरह के भाग्य का सामना करना पड़ा। हालांकि, एक और संशोधन दायर किए जाने पर, अपीलकर्ता सफल रहा और वित्तीय आयुक्त ने 21 नवंबर 1967 के अपने आदेश द्वारा नीचे दिए गए राजस्व अधिकारियों के आदेशों को रद्द कर दिया और किरायेदारों के आवेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा आयोजित भूमि का क्षेत्र उसके अनुमेय क्षेत्र के भीतर आता है और परिणामस्वरूप वह एक छोटा भूस्वामी था। वित्तीय आयुक्त के इस आदेश को रिट याचिका के माध्यम से लागू किया गया था, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिन्होंने माना है कि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण के मद्देनजर, अपीलकर्ता अपने पिता सुबा मल से विरासत में मिले क्षेत्र के संबंध में परंतुक (ii) के प्रावधानों का लाभ नहीं उठा सकता था और परिणामस्वरूप वह एक छोटा भूस्वामी नहीं था, अधिनियम के प्रावधानों के तहत।

3. इन अपीलों के समर्थन में श्री राम रंग के तर्क का सार यह है कि अपीलकर्ता का मामला अधिनियम की धारा 2 (3) (ii) (बी) के दायरे में आता है और उसके द्वारा धारण किया गया कुल क्षेत्र उसके अनुमेय क्षेत्र के भीतर होने के कारण वह परिणामस्वरूप एक छोटा भूस्वामी है। इस विवाद के समर्थन में पहले अधिनियम की धारा 2 (11) में 'विस्थापित व्यक्ति' की परिभाषा का संदर्भ दिया गया है, जिसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि अपीलकर्ता अपने आप में एक विस्थापित व्यक्ति है। धारा 2 (1) में भूस्वामी की परिभाषा पर भरोसा करते हुए, जिसमें एक आवंटी शामिल है, वकील ने पूर्वी पंजाब विस्थापित व्यक्ति (भूमि पुनर्स्थापन) अधिनियम, 1949 की धारा 2 (बी) के तहत एक आवंटी की परिभाषा को आगे बढ़ाने में मदद की, जिसमें उक्त शब्द को आवंटी के उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधियों और उप-पट्टेदारों को भी शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर, तनावपूर्ण तर्क की प्रक्रिया द्वारा, यह तर्क दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता एक विस्थापित व्यक्ति और अधिनियम के तहत एक भूस्वामी होने के नाते पूर्वी पंजाब विस्थापित व्यक्ति (भूमि पुनर्स्थापन) अधिनियम, 1949 में परिभाषा के आधार पर अपने पिता से विरासत में मिली भूमि का आवंटी भी होगा। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि उत्तराधिकारी के रूप में सूबा मल से विरासत में मिले क्षेत्र की सीमा तक उन्हें वहां का आवंटी माना जाएगा और उक्त भूमि कानून की नजर में एक विस्थापित व्यक्ति के रूप में उनके पक्ष में आवंटन है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा लगता है कि चेतन दास एक आवंटी के उत्तराधिकारी होने के नाते अपने पिता की तरह ही एक आवंटी हैं और उन्हें विरासत में मिली जमीन को सभी उद्देश्यों के लिए आवंटित माना जाना चाहिए।

4. वर्तमान मामले में मुद्दे का सार यह है कि क्या अपीलकर्ता को एक विस्थापित व्यक्ति माना जा सकता है जिसे अपने पिता सुबामल से विरासत में मिली भूमि के क्षेत्र के संबंध में अधिनियम की धारा 2 (3) (ii) के तहत भूमि आवंटित की गई है। प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए, सबसे पहले अधिनियम और विस्थापित व्यक्ति (पुनर्स्थापन) अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक है, जिस पर विद्वान वकील ने भरोसा किया है: -

"2(1) 'भूस्वामी का अर्थ पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का अधिनियम XVII) में इस प्रकार परिभाषित व्यक्ति से है, और इसमें पूर्वी पंजाब विस्थापित व्यक्ति (भूमि पुनर्स्थापन) अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम XXXVI) की धारा 2 के खंड (बी) और (सी) में परिभाषित एक 'आवंटी' और 'पट्टेदार' शामिल होंगे, जिसे बाद में 'पुनर्वास अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है।

* * * *

3.एक भूस्वामी या किरायेदार के संबंध में 'अनुमेय क्षेत्र' का अर्थ है तीस मानक एकड़ और जहां ऐसे तीस मानक एकड़ को साधारण एकड़ में परिवर्तित करने पर साठ एकड़ से अधिक हो जाता है, तो वो साठ एकड़:

बशर्ते कि -

(i)अनुमेय क्षेत्र की गणना करते समय इस अधिनियम के प्रारंभ में किसी बाग के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र को ध्यान में नहीं रखा जाएगा;

(ii) एक विस्थापित व्यक्ति के लिए -

(a) जिसे पचास मानक एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है, अनुमेय क्षेत्र पचास मानक एकड़ या एक सौ साधारण एकड़ होगा, जैसा भी मामला हो,

(b) जिसे तीस मानक एकड़ से अधिक, लेकिन पचास मानक एकड़ से कम भूमि आवंटित की गई है, अनुमेय क्षेत्र उसके आवंटित क्षेत्र के बराबर होगा,

(c) यदि किसी को तीस मानक एकड़ से कम भूमि आवंटित की गई है, तो अनुमेय क्षेत्र तीस मानक एकड़ होगा, जिसमें कोई अन्य भूमि या उसका हिस्सा, यदि कोई है, शामिल होगा जो उसके पास है।

स्पष्टीकरण- किसी विस्थापित व्यक्ति के अनुमेय क्षेत्र का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, परंतुक (ii) के प्रावधान विस्थापित व्यक्ति के उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें भूमि आवंटित की गई है।

"विस्थापित व्यक्ति (भूमि पुनर्स्थापन) अधिनियम।

2 इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो-

(a) * * . * *

(b)'आवंटी' का अर्थ है एक विस्थापित व्यक्ति जिसे 8 जुलाई, 1949 को पूर्वी पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 4892/एस के साथ प्रकाशित शर्तों के तहत संरक्षक द्वारा भूमि आवंटित की गई है, और इसमें उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि और उप-पट्टेदार शामिल हैं;

(c)'विस्थापित व्यक्ति' का अर्थ है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शामिल क्षेत्रों में भूमि धारक या पंजाबी निष्कर्षण का व्यक्ति जो उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध या बलूचिस्तान या उपरोक्त किसी भी प्रांत से सटे किसी भी राज्य में भूमि रखता है और पाकिस्तान में शामिल हो गया है, और जो 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान में शामिल है, नागरिक अशांति, या इस तरह की गड़बड़ी के डर या देश के विभाजन के कारण उक्त क्षेत्रों में अपनी भूमि को छोड़ दिया गया या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।

(d)* * *."

जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अपीलकर्ता के विद्वान वकील की प्राथमिक निर्भरता उपरोक्त धारा 2 (3) (ii) (बी) पर है। अब श्री राम रंग के तर्क में भ्रम यह है कि यह इस प्रावधान के महत्वपूर्ण शब्दों को अनदेखा करता है जो *'विस्थापित व्यक्ति, जिसे भूमि आवंटित की गई है'* को संदर्भित करता है। यह स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि विस्थापित व्यक्ति इस खंड के दायरे में होना चाहिए जिसे अधिकारियों द्वारा मूल रूप से भूमि आवंटित की गई है। इस प्रावधान की सीधी भाषा में यह परिकल्पना की गई है कि विस्थापित व्यक्ति वह होना चाहिए जिसे पहला आवंटन मूल रूप से किया गया हो। हमारे विचार में वाक्यांश "जिसे भूमि आवंटित की गई है" इसके दायरे में मूल आवंटी के उत्तराधिकारी को शामिल नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसा उत्तराधिकारी अपनी उपाधि विरासत से प्राप्त करता है, न कि आवंटन से। संदर्भ और प्रावधान की भाषा का बारीकी से अध्ययन करने पर हमारा विचार है कि आवंटी से विरासत मूल आवंटी द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष आवंटन से अलग है। वर्तमान मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मूल आवंटी अपीलकर्ता के पिता सूबा मल थे। उनकी मृत्यु के बाद, इंतक़ाल नंबर 300 के तहत, अपीलकर्ता और उनके एक अन्य भाई को मूल आवंटी की जमीन विरासत में मिली। जाहिर है, इन परिस्थितियों में, भाषा को तनाव दिए बिना और उसके साथ हिंसा किए बिना, यह संभवतः नहीं कहा जा सकता है कि चेतन दास को खुद जमीन आवंटित की गई थी। एक आवंटी से विरासत और मूल आवंटी को सीधे आवंटन संभवतः पर्यायवाची शब्द

नहीं हो सकते हैं।.

5. अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रावधान पर रखी गई व्याख्या से भी विसंगतिपूर्ण परिणाम होंगे। अपीलकर्ता दोहरी क्षमता में खड़ा है क्योंकि वह प्रत्यक्ष आवंटन का प्राप्तकर्ता है और उसे अपने पिता मूल आवंटी, से एक क्षेत्र विरासत में मिला है। जाहिर है कि उसी संदर्भ में वाक्यांश "जिसे भूमि आवंटित की गई है" को दो अलग-अलग अर्थ नहीं दिए जा सकते हैं ताकि 1 मानक एकड़ 143 इकाइयों के क्षेत्र के अपीलकर्ता को प्रत्यक्ष आवंटन और आगे मूल आवंटी सुबा मल से विरासत के रूप में उसे और उसके भाई को जो मिला दोनों को एक ही परिभाषा में समीहिलित किया जा सके। एक ही वाक्यांश विज्ञान संभवतः इन दो अलग-अलग स्थितियों को कवर नहीं कर सकता है।

6. अपीलकर्ता के रास्ते में एक और गंभीर लगभग घातक बाधा अधिनियम की धारा 2 (3) (ii) का स्पष्टीकरण है। यह स्पष्टीकरण उप-धारा (3) का हिस्सा नहीं था जब इसे मूल रूप से 1955 के पंजाब अधिनियम 11 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह स्पष्टीकरण 1962 के पंजाब अधिनियम संख्या 14 द्वारा अधिनियम में डाला गया था। इस अधिनियम को शामिल करने का उद्देश्य स्पष्ट प्रतीत होता है। उद्देश्य स्पष्ट रूप से इस स्थिति को स्पष्ट करना था कि विस्थापित व्यक्ति को कानून द्वारा दी गई एक बड़े अनुमेय क्षेत्र की रियायत केवल मूल आवंटियों के लिए थी, न कि उसके उत्तराधिकारियों के लिए। यह स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट शब्दों में किया गया था, जिसने स्पष्ट रूप से मूल आवंटियों और उनके उत्तराधिकारियों के बीच एक रेखा खींची थी। यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि परंतुक (ii) के प्रावधान विस्थापित व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें भूमि मूल रूप से आवंटित की गई थी। श्री राम रंग द्वारा उठाया गया विवाद वास्तव में इस स्पष्टीकरण को सम्मिलित करने को पूरी तरह से निरर्थक और उद्देश्यहीन बना देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री राम रंग ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि मूल आवंटी के उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी स्वयं उस व्यक्ति के समान स्थिति में हैं - जिसके लिए वे सफल होते हैं। इस तरह की व्याख्या सीधे स्पष्टीकरण की सरल भाषा में व्यक्त विधायिका के स्पष्ट इरादे को पराजित करेगी। हमने विद्वान वकील से एक ऐसी स्थिति की कल्पना करने के लिए कहा था जिसमें उक्त स्पष्टीकरण प्रभावी हो सकता है। श्री राम रंग द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि वह ऐसी किसी भी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते थे और उन्होंने शब्दों में प्रस्तुत किया कि स्पष्टीकरण अर्थहीन और पूरी तरह से अप्रभावी था। व्याख्या के स्थापित सिद्धांत के सामने इस तरह के विवाद को स्वीकार करना असंभव है कि क़ानून के प्रत्येक शब्द को एक अर्थ दिया जाना चाहिए और उसके किसी भी हिस्से को निरर्थक नहीं समझा जाना चाहिए।

7. उपरोक्त उपबंधों की हम जो व्याख्या करना चाहते हैं , **उसे मुंशी राम *बनाम* वित्तीय आयुक्त हरियाणा और अन्य**[1] *के मामले में पूर्ण पीठ की टिप्पणियों से समर्थन प्राप्त होता* है ।। उस मामले में 30 मानक एकड़ के रूपांतरण फार्मूले के प्रभाव पर विचार करने के अलावा, पूर्ण पीठ ने स्पष्टीकरण के अर्थ और मूल आवंटी के उत्तराधिकारियों की स्थिति पर भी ध्यान दिया। इसमें मूल आवंटी बिशन दास की मृत्यु हो गई थी और उसके बेटों ने विस्थापित व्यक्तियों के रूप में भूमि के प्रत्यक्ष आवंटी होने का दावा किया था। इस तरह के विवाद को खारिज करते हुए शमशेर बहादुर न्यायमूर्ति ने निम्नानुसार कहा: –

> " एक सख्त व्याख्या पर ऐसा प्रतीत होता है कि विस्थापित व्यक्ति का दर्जा बिशन डार को दिया जा सकता है और केवल उसे ही दिया जा सकता है, जिसने भूमि धारण की थी और विभाजन के परिणामस्वरूप इसे छोड़ दिया था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्होंने पूर्वी पंजाब शरणार्थी (भूमि दावों का पंजीकरण) अधिनियम, 1948 के तहत दावा दायर किया था, जिसमें एक शरणार्थी को पुनर्वास अधिनियम में विस्थापित व्यक्ति के समान शब्दों में परिभाषित किया गया है। बिशन दास ने शरणार्थी के रूप में अपना दावा दायर किया है, एक ऐसा शब्द जिसे विस्थापित व्यक्ति के बराबर माना जाता है, अपीलकर्ताओं के लिए अब यह आग्रह करना अजीब है कि यह वे हैं जो अपने पिता के बजाय पुनर्वास अधिनियम के तहत विस्थापित व्यक्ति हैं। बिशन दास ने विस्थापित व्यक्ति की परिभाषा की आवश्यकताओं को पूरा किया और इस तरह से भूमि आवंटित किए जाने के बाद, उनके बेटों के पक्ष में भाषा नहीं फैलाई जा सकती है कि वे उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करें, जब उन्हें स्पष्टीकरण के तहत विशेष रूप से छोड़ दिया जाए।

और फिर, मेरे विद्वान भाई पी. सी. पंडित, न्यायमूर्ति, जो पीठ के सदस्य थे, ने पृष्ठ 930 पर इसी तरह के शब्दों में टिप्पणी की: –

> "1962 के पंजाब अधिनियम XIV द्वारा जोड़े गए इस परंतुक के स्पष्टीकरण (ii) में उनके मामले को पूरी तरह से शामिल किया गया है। इस स्पष्टीकरण में कहा गया है कि विस्थापित व्यक्ति के अनुमेय क्षेत्र का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, परंतुक (ii) के प्रावधान विस्थापित व्यक्ति के उत्तराधिकारियों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें भूमि आवंटित की गई थी। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, भूमि वास्तव में बिशन दास के नाम पर आवंटित की गई थी,

[1] 1967 P.L.R. 913.

जो एक विस्थापित व्यक्ति था और अपीलकर्ता उसके उत्तराधिकारी थे।

8. पूर्ण पीठ की उपरोक्त टिप्पणियों का सामना करते हुए, श्री राम रंग ने यह तर्क देने की कोशिश की थी कि जो तर्क वह अब हमारे सामने उठाना चाहते हैं, उसे पीठ के समक्ष उस रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था और उपरोक्त टिप्पणियां सही कानूनी स्थिति निर्धारित नहीं करती हैं। यह भी तर्क दिया गया कि पूर्ण पीठ मामले के फैसले के खिलाफ एक अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन दोनों कारणों में से कोई भी उन स्पष्ट टिप्पणियों से विचलित होने का कोई वारंट नहीं है जो हमारे लिए बाध्यकारी हैं, और इसके तर्क को न मानने के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है।

9. श्री राम रंग के लिए निष्पक्षता से हम उन तीन मामलों पर ध्यान देंगे जिन पर उन्होंने भरोसा करने की मांग की थी। ***वजीर चंद* बनाम *राज्य***[2] स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के लिए कोई मदद नहीं है क्योंकि उक्त मामले में निर्णय पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1962 द्वारा स्पष्टीकरण को शामिल करने से बहुत पहले दिया गया है। **रोशन दास बनाम वित्तीय आयुक्त, पंजाब और अन्य**[3] *के मामले में* महाजन न्यायमूर्ति की एकल पीठ का फैसला पूरी तरह से अलग है। इसमें मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर यह माना गया था कि *किसी व्यक्ति द्वारा अपने भाई के नाम पर किए गए बेनामी आवंटन को वास्तव में वास्तविक मालिक को आवंटन माना जा सकता है।* जाहिर है कि वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और आगे जिस स्पष्टीकरण का पहले संदर्भ दिया गया है, वह उस मामले में व्याख्या का विषय कभी नहीं था। *गुरदेव सिंह न्यायमूर्ति द्वारा दिए गए एक अन्य एकल पीठ के फैसले* ***पत राम* बनाम *पंजाब राज्य***[4] के गहन अवलोकन पर हम पाते हैं कि न तो तथ्यों और न ही उनके अनुपात का वर्तमान से दूर-दूर तक कोई लेना-देना है।

10. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हमें अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क में कोई दम नहीं दिखता है और दोनों अपीलों को विफल होना चाहिए।

11. हालांकि, हमें श्री राम रंग द्वारा उठाई गई एक सहायक प्रार्थना में दम नजर आता है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्चतम राजस्व न्यायाधिकरण, अर्थात्, वित्तीय आयुक्त ने माना था कि वह एक छोटा भूस्वामी था और परिणामस्वरूप प्रतिवादी-किरायेदार अपनी किरायेदारी में

[2] C.W.1122 of 1957 decided on 1st September 1958
[3] 1964 L.L.T.120.
[4] C.W.No. 1433 of 1964

शामिल भूमि खरीदने के हकदार नहीं थे। यह तर्क दिया जाता है कि निचली राजस्व अदालतों में अपीलकर्ता ने इस दृढ़ स्थिति पर प्रामाणिक रूप से मुकदमा दायर किया था कि वह वास्तव में एक छोटा भूस्वामी था और ऐसी स्थिति में भूमि का आरक्षण या चयन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह आगे तर्क दिया गया है कि इस बिंदु पर न्यायिक राय में तीव्र भिन्नता बनी हुई है कि अपीलकर्ता एक छोटा या बड़ा भूस्वामी होगा जब तक कि इस मामले को अंततः हाल ही में इस न्यायालय की आधिकारिक घोषणाओं द्वारा तय नहीं किया जाता है । ऐसी स्थिति में यह दावा किया जाता है कि अपीलकर्ता उस समय से अपनी भूमि का आरक्षण करने का हकदार है जब उसे एक बड़ा भूमिधारक घोषित किया जाता है और वर्तमान मामले में यह विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से होगा।

12. उपर्युक्त विवाद को **माना राम और अन्य *बनाम* वित्तीय आयुक्त, हरियाणा और अन्य**[5] *में टिप्पणियों से समर्थन प्राप्त होता* है, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया है: -

> * ** बड़े भू-स्वामी को अपनी व्यक्तिगत खेती के लिए क्षेत्र का चयन या आरक्षित करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और वह अपने अधिकार का प्रयोग तभी कर सकता है जब वह एक बड़ा भूस्वामी पाया जाता है। इस अधिकार का उपयोग एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता था जिसे गलत तरीके से या सही तरीके से एक छोटे भूमि मालिक के रूप में घोषित किया गया था।

इसी आशय की टिप्पणियां **राम चंद *बनाम* मुंशी राम और अन्य**[6] *में सोढ़ी न्यायमूर्ति की टिप्पणियां हैं*, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हम यह मानते हैं कि अपीलकर्ता जिसे अब एक बड़ा भूमि धारक माना गया है, वह पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण करने का हकदार है।

13. इन टिप्पणियों के साथ अपील विफल हो जाती है और लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज `कर दी जाती है।

[5] 1970 P.L.J.676
[6] 1969 P.L.J. 74

पी. सी. पंडित, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी